

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
07.02.2024 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 842 का उत्तर

रेलवे में कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना

842. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह देखते हुए कि रेलवे क्षेत्र की 173 परियोजनाओं में से 114 परियोजनाएं विलम्ब से चल रही हैं, सरकार का इस क्षेत्र में विलम्ब से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो क्या विद्युतीकरण का बोझ कोयला जैसे जैव ईंधनों से प्राप्त विद्युत पर स्थानांतरित किया जाएगा; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे में कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को लोक सभा में श्री बैन्नी बेहनन के अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, लागत में साक्षेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी का जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) को पूरा करने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग कुल 126.91 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से लगभग केवल 25.45 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए गए थे लेकिन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफलता नहीं मिली थी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए केरल राज्य सरकार की सहायता की आवश्यकता है।

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, पूरे भारतीय रेल में लगभग 7.18 लाख करोड़ रुपये लागत वाली 46,360 किलोमीटर लंबाई की 459 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (नई लाइन, आमामान परिवर्तन और दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिसमें से मार्च, 2023 तक 11,872 किलोमीटर लंबाई कमीशन की जा चुकी है।

पूरे भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन नीचे दर्शाया गया है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	11,527 करोड़ रु./वर्ष	-
2023-24	67,199 करोड़ रु.	लगभग 6 गुणा

भारतीय रेल में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण खंडों को कमीशनिंग करने का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

अवधि	कुल कमीशनिंग	प्रति दिन कमीशनिंग	वर्ष 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में कमीशनिंग में वृद्धि
2009-14	7,599 किलोमीटर	4.2 किलोमीटर/दिन	-
2022-23	5,243 किलोमीटर	14.4 किलोमीटर/दिन	लगभग 3.4 गुणा

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरी और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 2014 के बाद से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ): भारतीय रेल ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की हैं जिनमें पूर्ण रूप से तीन फेज वाले इलेक्ट्रिक इंजनों और रिजेनरेटिव विशेषताओं वाले ईएमयू/एमईएमयू का उत्पादन करना, हेड ऑन जेनरेशन (एचओजी) तकनीक का उपयोग, भवनों

और सबारीडिब्बों में एलईडी लाइटों का उपयोग और स्टार रेटेड उपकरणों का उपयोग जैसे ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जिन प्रमुख उपाय की पहचान की गई है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली की खरीद, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन में शीफ्ट करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है।

अपने बड़ी लाइन (बीजी) मार्गों के लिए 100% विद्युतीकरण करने की योजना के साथ, भारतीय रेल यथासंभव डीजल इंजन से विद्युत इंजन में बदलने की योजना है।

\*\*\*\*\*